जलवायु वित्त पर ओईसीडी रिपोर्ट

द हिंदू

पेपर-III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी)

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) द्वारा प्रकाशित एक नई रिपोर्ट से पता चला है कि आर्थिक रूप से विकसित देश 2021 में विकासशील देशों की जलवायु शमन और अनुकूलन आवश्यकताओं के लिए संयुक्त रूप से प्रति वर्ष 100 अरब डॉलर जुटाने के अपने वादे से पीछे रह गए हैं - एक साल पहले। 2020 की समय सीमा। रिपोर्ट में कहा गया है कि विकसित देशों ने 2021 में 89.6 बिलियन डॉलर जुटाए और 2020 की तुलना में 2021 में अनुकूलन के लिए वित्त में 14% की गिरावट आई।

OECD रिपोर्ट क्यों महत्वपूर्ण है?

ओईसीडी मुख्य रूप से अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, कनाडा और अन्य सहित समृद्ध देशों का एक समूह है। इस प्रकार, यह रिपोर्ट अगले सप्ताह संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में COP28 जलवायु वार्ता से पहले जलवायु वित्त के बारे में उनके विचार की एक झलक पेश करती है, जहां यह विषय विवाद का मुख्य विषय होने की उम्मीद है।

यह रिपोर्ट 2020 में ग्लासगो में COP26 वार्ता में विकसित देशों के समूह द्वारा अनुकूलन वित्त को दोगुना करने की प्रतिज्ञा की पृष्ठभूमि में भी आई है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के दलों ने भी ग्लासगो में, "गहरे अफसोस के साथ" कहा था कि विकसित देशों का समूह 2020 में तय समय में 100 अरब डॉलर के जलवायु वित्त लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया। पर्याप्त जलवायु वित्त विकासशील देशों में जलवायु शमन (जैसे नवीकरणीय ऊर्जा के साथ उत्सर्जन में कमी) और अनुकूलन आवश्यकताओं (जैसे जलवायु-लचीली कृषि को विकसित करना और प्रोत्साहित करना) को संबोधित करने की क्षमता को कम करता है, और दुनिया के गरीब देशों के बीच इस विश्वास को कम करता है कि विकसित दुनिया जलवायु संकट से निपटने के बारे में गंभीर है।

जलवायु वित्त का लेखा-जोखा कैसे किया जाता है?

ओईसीडी रिपोर्ट से पता चला है कि 2021 में सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा द्विपक्षीय और बहुपक्षीय चैनलों के माध्यम से जुटाए गए 73.1 बिलियन डॉलर में से 49.6 बिलियन डॉलर ऋण के रूप में प्रदान किए गए थे। हालाँकि रिपोर्ट उन्हें प्रदान की जाने वाली दरों के आधार पर वर्गीकृत नहीं करती है, लेकिन अन्यत्र उपलब्ध डेटा इस बात पर प्रकाश डालता है कि अमीर देश अपने जलवायु वित्त दायित्वों को पूरा करने के लिए वाणिज्यिक दरों पर ऋण पर किस हद तक निर्भर हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिकी गैर-लाभकारी अनुसंधान समूह क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव द्वारा 2011 और 2020 के बीच वैश्विक जलवायु वित्त प्रवाह के आकलन में पाया गया कि 61% जलवायु वित्त ऋण के रूप में प्रदान किया गया था, जिसमें से केवल 12% रियायती ब्याज दरों पर था।

इसलिए, जब ओईसीडी रिपोर्ट में कहा गया है कि सार्वजनिक जलवायु वित्तपोषण का दो-तिहाई हिस्सा ऋण के रूप में प्रदान किया गया था, तो इसका मतलब है कि इस तरह के वित्तपोषण से जुड़ी शर्तें गरीब देशों में ऋण तनाव को और बढ़ा सकती हैं। यह ओईसीडी रिपोर्ट की भी आलोचना है क्योंकि यह कुल जलवायु वित्त आंकड़ों पर पहुंचने पर अनुदान के बराबर नहीं, बल्कि अंकित मूल्य पर ऋण पर विचार करती है। इसका मतलब यह है कि जबकि गरीब देश पुनर्भुगतान और ब्याज के लिए पैसा खर्च करते हैं, ऋण को अभी भी विकसित दुनिया द्वारा प्रदान किए गए जलवायु वित्त के रूप में गिना जाता है।

अतिरिक्तता क्या है?

ओईसीडी रिपोर्ट में एक अन्य मुद्दा अतिरिक्तता से संबंधित है। यूएनएफसीसीसी का कहना है कि विकसित देश "सम्मेलन के तहत अपने दायित्वों के अनुपालन में विकासशील देशों की पार्टियों द्वारा किए गए सहमत पूर्ण लागत को पूरा करने के लिए नए और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन प्रदान करेंगे"। इसका मतलब यह है कि विकसित देश जलवायु संबंधी जरूरतों को वित्तपोषित करने के लिए विदेशी विकास सहायता (ओडीए) में कटौती नहीं कर सकते क्योंकि इससे प्रभावी रूप से पीटर को पॉल को भुगतान करने में दिक्कत होगी। वास्तविक दुनिया के संदर्भ में, इसका मतलब होगा सौर पैनल स्थापित करने, कहने के लिए उस धन को पुनः आवंटित करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल के लिए समर्थन में कटौती करना।

"नए और अतिरिक्त वित्त" का अर्थ यह भी है कि विकसित देश दोहरी गिनती नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, एक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना किसी क्षेत्र में उत्सर्जन में कमी और समग्र विकास दोनों में योगदान दे सकती है। हालाँकि, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार, दाता देश ऐसी फंडिंग को ओडीए और जलवायु वित्त दोनों के रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते क्योंकि यह "नए और अतिरिक्त" मानदंड को पूरा नहीं करेगा। फिर भी वे ऐसा करते हैं। कुछ साल पहले, यूरोपीय संघ के अधिकारियों ने जलवायु वित्त के रूप में विकास सहायता की दोहरी गिनती की बात स्वीकार की थी।

जलवायु वित्त के रूप में क्या गिना जाता है?

वर्तमान में, 'जलवायु वित्त' की कोई आम सहमति वाली परिभाषा नहीं है क्योंकि विकसित देशों ने इसे अस्पष्ट रखने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए, पिछले साल मिस्र में COP27 में, ऑस्ट्रेलिया और यूके ने 'जलवायु वित्त' को परिभाषित करने के लिए चर्चा को समाप्त करने की भी मांग की थी। ग्लासगो में COP26 से पहले, अमेरिका ने स्विट्जरलैंड, स्वीडन और कुछ अन्य विकसित देशों के साथ, एक सामान्य परिभाषा पर बहस को रोकने के प्रयास का नेतृत्व किया।

कथित तौर पर निश्चित स्पष्टता की कमी के कारण एशिया भर में चॉकलेट और जिलेटो स्टोरों की फंडिंग और हैती में एक तटीय होटल विस्तार को जलवायु वित्त के रूप में टैग किए जाने जैसी हास्यास्पद स्थितियाँ पैदा हुई हैं। अस्पष्टता अमीर देशों के पक्ष में काम करती है क्योंकि यह ओडीए और उच्च लागत वाले ऋणों सहित किसी भी फंडिंग को जलवायु वित्त के रूप में मनमाने ढंग से वर्गीकृत करने के लिए दरवाजा खुला छोड़ देती है और एक स्पष्ट परिभाषा के कारण होने वाली जांच से बच जाती है। इसलिए, जबकि विकसित देश दावा कर सकते हैं कि उन्होंने जलवायु वित्त में अरबों डॉलर प्रदान किए हैं, यह जानने के लिए वास्तविक प्रवाह की जाँच की जानी चाहिए कि क्या वे विकासशील देशों में जलवायु शमन और अनुकूलन में गए या कुछ और।

विकासशील देशों को कितनी वित्तीय सहायता की आवश्यकता है?

प्रारंभिक और अभी तक असत्यापित डेटा के आधार पर नवीनतम ओईसीडी रिपोर्ट का दावा है कि 100 बिलियन डॉलर का लक्ष्य 2022 में पूरा होने की संभावना है। लेकिन डेटा को न तो अंतिम रूप दिया गया है और न ही प्रकाशित किया गया है, और सलाह दी गई है कि इसे दूर किया जाए। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि COP15 वार्ता में $100 बिलियन का आंकड़ा हवा में आया और यह इस आकलन पर आधारित नहीं है कि विकासशील देशों को वास्तव में कितने जलवायु निवेश की आवश्यकता है। ओईसीडी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 तक, विकासशील देशों को जलवायु निवेश में प्रति वर्ष लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता होने का अनुमान है, जो 2026 और 2030 के बीच हर साल लगभग 2.4 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ जाएगा।

निजी क्षेत्र क्या भूमिका निभा सकता है?

चुनौती के पैमाने को पूरा करने के लिए, अमेरिकी जलवायु दूत जॉन केरी और विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा जैसे लोगों ने नियमित रूप से निजी क्षेत्र की भूमिका पर जोर दिया है।

लेकिन ओईसीडी रिपोर्ट ने खुद ही ऐसी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, जिससे पता चला कि जलवायु कार्रवाई के लिए निजी वित्तपोषण एक दशक से स्थिर है, जबकि बहुपक्षीय चैनलों, बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) और बहुपक्षीय जलवायु निधि दोनों से सार्वजनिक फंडिंग में इसी अवधि में वृद्धि हुई है। विशेष रूप से 2021 में, यह पता चला कि 2020 में मामूली गिरावट के बाद निजी फंडिंग 2019 के स्तर पर वापस आ गई।

पाठ्यक्रम-सुधार उपाय के रूप में, ओईसीडी रिपोर्ट ने सरकारी हस्तक्षेप के साथ जोखिम को कम करने का सुझाव दिया और एमडीबी से अपने मुख्य उद्देश्य के हिस्से के रूप में निजी वित्त जुटाने की रणनीतियों को एकीकृत करने का आह्वान किया। इसका तर्क यह है कि निजी क्षेत्र जलवायु कार्रवाई को सक्षम करने में मदद कर सकता है लेकिन इसके लिए "व्यक्तिगत परियोजनाओं को समर्थन देने, प्रोत्साहित करने और जोखिम कम करने के साथ-साथ विकासशील देशों में निवेश के लिए आवश्यक स्थितियां बनाने के लिए सरकारों और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है।"

लेकिन आज तक, ऐसे कोई संकेत नहीं हैं कि निजी क्षेत्र अपने जलवायु निवेश को बड़े पैमाने पर बढ़ाने में रुचि रखता है। समस्या विशेष रूप से जलवायु अनुकूलन के लिए बदतर है, क्योंकि इस क्षेत्र में निवेश उस तरह का उच्च रिटर्न उत्पन्न नहीं कर सकता है जो निजी निवेशक चाहते हैं और जो शमन क्षेत्र - जैसे सौर या पवन फार्म - उत्पन्न कर सकता है।

दिन के अंत में, गेंद वापस सार्वजनिक वित्त पोषण के पाले में चली जाती है, यानी विकसित दुनिया की सरकारों और बहुपक्षीय विकास बैंकों के पाले में। ओईसीडी रिपोर्ट से पता चलता है कि जो लोग भविष्य में जलवायु कार्रवाई के लिए उच्च निजी वित्त पोषण की आशा रखते हैं, वे भी मानते हैं कि यह सरकारें और एमडीबी हैं जो यहां सक्षम पक्ष हैं।

संभावित प्रश्न (Expected Question)

प्रश्न : जलवायु वित्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. पिछले साल मिस्र में कॉप 27 में, ऑस्ट्रेलिया और यूके ने 'जलवायु वित्त' को परिभाषित किया।
2. वर्तमान में, 'जलवायु वित्त' की कोई आम सहमति वाली परिभाषा नहीं है

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 ना ही 2

Que. Consider the following statements in the context of climate finance

1. Last year at COP 27 in Egypt, Australia and the UK defined 'climate finance'.
2. Currently, there is no agreed definition of 'climate finance'.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) Only 1

(b) Only 2

(c) Both 1 & 2

(d) Neither 1 nor 2

उत्तर : b

संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न : जलवायु वित्त क्या है और जलवायु वित्तपोषण की आवश्यकता क्यों है? निजी क्षेत्र इसमें क्या भूमिका निभा सकता है?

उत्तर का दृष्टिकोण:

- उत्तर के पहले भाग में जलवायु वित्त और जलवायु वित्तपोषण की आवश्यकता की चर्चा करें।
- दूसरे भाग में निजी क्षेत्र इसमें क्या भूमिका निभा सकता है, उसकी चर्चा करें।
- अंत में आगे की राह दिखाते हुए निष्कर्ष दें।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।